10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 1

दैनिक

नज़रिया खबर

भारत सरकार के डीएवीपी व राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त

RNI:UTTHIN/2008/25052

वर्ष:18 | अंक: 11 | देहरादून, गुरुवार 10 जुलाई, 2025 | पृष्ठ: 08 | मूल्य: 1/रु. प्रति

न्यूज डायरी

फिनटेक दिग्गज प्रभाकर तिवारी लॉन्च करेंगे 'प्रोजेक्ट ड्रोन'

देहरादून। भारत के फिनटेक उद्योग के जाने–माना चेहरा और डिजिटल ब्रोकिंग अनुभव के अग्रणी, प्रभाकर तिवारी अब अपने नए स्टार्टअप वेंचर 'प्रोजेक्ट ड्रोन' के साथ वेल्थटेक स्पेस में कदम रखने जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में उन्हें रणनीतिक साझेदार के रूप में सूचीबद्ध वित्तीय सेवा कंपनी शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड (एनएसईरू शेयर इंडिया, बीएसई 540725) का समर्थन प्राप्त है। यह वेंचर आवश्यक विनियामक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में है। प्रोजेक्ट ड्रोन का उद्देश्य भारत के उभरते और मास अफ्लुएंट निवेशकों के लिए, विशेष रूप से टियर 2, 3 और 4 शहरों में, स्मार्ट और तकनीक–आधारित वेल्थ सॉल्यूशन्स प्रदान करना है। यह प्लेटफॉर्म बिहेवियरल फाइनेंस एल्गोरिदम, स्थानीय भाषाओं में इंटरफेस, और इंस्टिट्यूशनल–ग्रेड टूल्स के माध्यम से रीटेल निवेशकों को सशक्त बनाएगा।

अर्बन क्रूजर हाइराइडर के लिए विशेष प्रेस्टीज पैकेज पेश किया

देहरादून। ग्राहकों की खुशी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी लोकप्रिय सेल्फ–चार्जिंग हाइब्रिड एसयूवी–अर्बन क्रूजर हाइराइडर के लिए सीमित अवधि का प्रेस्टीज पैकेज पेश किया है । एसयूवी के पहले से ही बोल्ड व परिष्कृत आकर्षण को और बढ़ाने के लिए सोच–समझकर डिजाइन किया गया, यह विशेष एक्सेसरी बंडल ग्राहकों को रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए स्टाइल, उपस्थिति और कार्यक्षमता की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। प्रत्येक ऐसेसरी को हाइराइडर के विशिष्ट एसयूवी चरित्र के साथ सहजता से मेल खाने के लिए तैयार किया गया है–जो इसके मस्कुलर स्टांस, क्रोम हाइलाइट्स और आकर्षक सिलुएट को बढ़ाता है, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा और स्थायित्व भी प्रदान करता है।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे डीएमः धामी

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में जिलाधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनाते हुए, उन्हें संबंधित शिकायतों का निस्तारण करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007' को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जाए। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता को उनके बच्चों, बालिक पोते–पोतियों अथवा संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण–पोषण की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर कुल 13 अपीलीय भरण–पोषण अधिकरण एवं सब डिवीजन स्तर पर 69 से अधिक भरण–पोषण अधिकरण कार्यरत हैं। जहां भरण–पोषण की राशि अधिकतम ध्10,000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं, इसलिए उन पर इस कानून को सख्ती से अमल में लाते हुए, वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। साथ ही तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी भरण पोषण संबंधित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन भरण–पोषण अधिकारी के रूप में जिम्मेदार बनाए गए हैं। संपत्ति हस्तांतरण में सुरक्षा प्रावधानः कानून के तहत यदि कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करता है, लेकिन इसके बाद तय शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित करते हुए, संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएंः बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं। जहां कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं।

शेष खबर पेज आठ पर देखे

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर बद्री–केदार मंदिर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों ने चारधाम यात्रा के सफल, सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मार्ग व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और समग्र प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के समर्पित कार्यों के परिणामस्वरूप यात्रियों को यात्रा के दौरान न केवल बेहतर सुविधा मिली, बल्कि सुरक्षा का भरोसा भी बना रहा।

राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, उत्तराखंड की मिली पहली जियोथर्मल पॉलिसी

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पीडब्ल्यूडी के तहत प्रदेश के बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही प्रदेश की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। यही नहीं, सतर्कता (विजिलेंस) विभाग को और मजबूत किए जाने को लेकर ढांचे में संशोधन किया गया है। विजिलेंस विभाग ने 20 नए पद बढ़ाए जाएंगे। इस तरह

विजिलेंस विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी। उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को दी मंजूरी। उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य में जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। नीति का उद्देश्य चिन्हित भू–तापीय ऊर्जा स्थलों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही भू–तापीय ऊर्जा के उत्पादन और विद्युत उत्पादन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष इस्तेमाल, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास में इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के माध्यम से भू–तापीय ऊर्जा के माध्यम से राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य के दीर्घकालिक पर्यावरणीय व ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान के माध्यम से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह नीति राज्य के सभी भू–तापीय परियोजनाओं पर लागू होगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में मौजूद पुलों के वाहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी दी है। सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सर्तकता विभाग ने 20 नए पद बढ़ाए गए है। विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 की गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है।

उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए कैबिनेट जाने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना उत्तराखण्ड में की जाएगी जिसके लिए बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक ने अपनी मंजूदी दे दी है।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 2

संपादकीय

क्या अब बिना नेटवर्क के भी होगी कॉलिंग, चलेगा इंटरनेट

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया कि अंतरिक्ष नियामक एजेंसी इन–स्पेस ने हरी झंडी दे दी है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है, जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले ईयूटेलसेट वनवेब और रिलायंस जियो को मंजूरी मिली थी। यह सेवा मंजूरी आठ अप्रैल से पांच साल की अवधि के लिए या जनरेशन 1 समूह के परिचालन जीवन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है। सेवाओं का क्रियान्वयन निर्धारित नियामकीय प्रावधानों और संबंधित सरकारी विभागों से अपेक्षित मंजूरी, अनुमोदन और लाइसेंस के अधीन है। स्टारलिंक जेन1 कॉन्स्टेलेशन एक वैश्विक मंडल है जिसमें 4,408 उपग्रह 540 किलोमीटर से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यह भारत में लगभग 600 गीगावाट प्रति सेंकंड 'जीबीपीएस' की क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। स्टारलिंक 2022 से ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय बाजार पर नजर गड़ाए हुए थी। स्टारलिंक पिछले महीने, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बाद भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी बन गई। हालांकि, जिन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुका है, उन्हें वाणिज्यिक उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में मूल्य निर्धारण और नियम व शर्तों पर अपनी सिफारिशें सरकार को विचार करने के लिए भेजी हैं। स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।

आज के समय 'कोउ नृप होय हमें का हानी' 'इससे क्या फर्क पड़ता है' का समय आ गया है

स्वामी कमलानंद (पूर्व सचिव भारत सरकार)

मेरे ख्याल से–
उत्तम खेती, मध्यम बान,
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान।
सुर नर मुनि सब के यह रीति। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति।

जैसे कई नीति ज्ञानवर्द्धक सिद्धांत है जो समय की परीक्षा में खरे उतरे हैं। हिन्द स्वराज में जो प्रश्न सभ्य समाज, शोषण व्यवस्था, विकास के मापदंड, मशीनीकरण की सीमा, भारत ने क्या खोया–पाया, प्राचीन मान्यताएं आदि ऐसे विषय हैं जो इस समय की सरकारी–असरकारी तथा असरकारी प्रयासों, प्रश्नों एवं समग्रवादी विकास में संतुलन स्थायित्व, स्वरोजगार जैसे विषयों को लेकर देखना जरूरी है।

कई महान हस्तियों, चिंतकों आदि के साथ चर्चा–परिचर्चा, सारांश ढूंढते समय निम्नलिखित कुछ निचोड़ मेरी समझ में आए। इसे एक समग्रवादी चर्चा के साथ वातावरण सृजन हेतु आप सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इसको व्यावहारिकता, सामयिकता के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार देने का कष्ट करें। स्वरोजगार, विकेन्द्रित, उद्यमिता, स्वावलंबन, स्वाभिमान आदि शब्द जैसे केवल कागज पर रह गए है। लगता है इनसे विश्वास प्रेम, सार्थकता, विध्वंसात्मक, शोषणात्मक नीतियों के कारण नहीं हो पा रहा है। हालांकि, हमारे आसपास आशावादी, प्रेरणादायी, प्रोत्साहनात्मक, स्वावलंबी आदि कई लोग हैं, जिनके अध्ययन से आशावादी माहौल बनता है। क्या ऐसे लेखक, पत्रकार, नेतृत्वदायक शिक्षक, सरकारी या गैर सरकारी हैं? क्या इनका पूरा सदुपयोग हो रहा है? क्या ये व्यवस्था को सुचारु बनाने में भागीदार हैं? क्या छेटे–छोटे प्रयासों में इनकी च्वजमदबल थंबजवत न्यूनतम आर्थिक खर्च में बढ़ाई जा सकती है? दूसरा प्रयास प्रासंगिकता परिभाषाओं को नए सिरे से नापना है। कई प्रचलित शब्द अपना मूल रूप खो चुके हैं एवं वर्तमान में शोषण के प्रामाणिक साधन बन गए हैं। विकास, गति, मानव संसाधन, तकनीक, मार्केट, आनंद संतुष्टता, उत्पादकता आदि शब्द पूर्णतरू दिशाविहीन शोषण के हथियार हो गए हैं। शोषण या पोषण, जड़ या चेतन, संगणित बनाम अंकगणित, नीति नियति जैसी श्रृंखलाएं स्वाभिमान से जुड़े प्रश्न परावलंबन परिप्रेक्ष्य से ही तौले–देखे जा रहे हैं। ढर्रे की व्यवस्था में सृजनात्मकता बड़ी लाइन बनाने का विश्वास शायद खो चुकी है। अतः परिभाषाएं विकास के समग्रवादी परिप्रेक्ष्य में पुनरावलोकन करना है। स्वरोजगार, उद्यमिता, पर्यावरणपूरकता, ऐसी हो कि ग्रामीण नियोजन व्यवस्था के लिए व्यावहारिक बन सके। आज के कंप्यूटर के युग में स्वरोजगारी अनुदान के बिना भी प्रगतिशील नेतृत्व गतिशील हो रहा है। ऐसे प्रयासों में नीतियों का बहुत बड़ा स्थान है। भारत जैसे देश में विविधताएं, विषमताएं तथा समस्याएं गंभीर हैं। इनके उत्तर भी स्थान, काल, स्तर को ध्यान में रखकर ही निकलेंगे।

पीएम से लेकर आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर हो सकता है महत्वपूर्ण कारक

थाईलैंड की पीएम व डोनाल्ड ट्रंप,नेतन्याहू,इंदिरा गांधी सहित अनेकों अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को न्यायपालिका के फैसलों का सामना करना पड़ा है

गोंदिया। वैश्विक स्तरपर सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के प्रेस को मिलाकर चार स्तंभ होते हैं। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका व मीडिया, जो अपने–अपने स्तरपर अपने–अपने कार्यक्षेत्र में पावरफुल होते हैं, परंतु अक्सर हम देखते हैं कि न्यायपालिका के पावरक्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य से लेकर पार्षद व विधायक से लेकर संसद तथा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री व स्टेट मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री व पूरी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते हैं,यांने अगर किसी भी कार्यक्षेत्र में कोई गड़बड़ी कानून का को तोड़ना उलंघन करना, भ्रष्टाचार करना या मानवाधिकार का हनन संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक क्षेत्र के पावर में आ जाते हैं।

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि साफ सुथरे ईमानदार व्यक्ति को डरने घबराने की जरूरत नहीं, परंतु भ्रष्टाचार गलत आचरण से तो न्यायिक दायरे में आना ही पड़ेगा। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्यों के मंगलवार 1 जुलाई 2025 को थाईलैंड की पीएम को वहां के न्यायालय की संविधान पीठ ने7ध्2 के बहुमत से 1 जुलाई 2025 से पीएम पद के कार्य से निलंबित कर दिया है,जब तक संवैधानिक पीठ अपना फैसला नहीं सुनाती। पूरी दुनियाँ के प्रशासकीय व राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि विश्व के अनेक बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, इंदिरा गांधी सहित अनेको नेताओं को इन न्यायिक शक्तियों का सामना करना पड़ा है जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे।

न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में खास से आम तक सभी व्यक्तियों को एक समान संहिता लागू होकर सजा या बरी होना खूबसूरती है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्धजानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, विश्व में न्यायालय का पावर,पीएम से लेकर एक आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

साथियों बात अगर हम थाईलैंड की पीएम को संविधान पीठ द्वारा 7ध्2 बहुमत से पद से निलंबित करने की करें तो, संवैधानिक न्यायालय ने पीएम पाइतोंग्तार्न शिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है।उनपर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है।इस बातचीत के लीक होने के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7–2 के अंतर से पीएम को पद से हटाया कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाई गईं तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है।पीएम ने खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वह पीएम के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे।किसी देश के पीएम को पद पर रहते हुए उसे निलंबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।

साथियों बात अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट को शक्तियों की प्रक्रिया का सामना करने की करें तो,अब तक अमेरिकी अदालतों ने ट्रम्प प्रशासन के कम से कम 180 कार्यकारी आदेशों और नीतियों पर स्थाई या अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। साथ ही, ट्रम्प ने खुद 11 प्रमुख फैसलों पर यू–टर्न लेते हुए पलटा है।रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने, संघीय कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी और विदेशी सहायता रोकने जैसे आदेशों को अवैध या असंवैधानिक ठहराया है।वहीं, ट्रम्प ने फेडरल फंडिंग फ्रीज, अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा और टैरिफ नीतियों जैसे फैसलों को कई बार बदला या वापस लिया है।ट्रम्प के वो आदेश जिन्हें कोर्ट ने बदला ट्रंप ने वॉयस ऑफ अमेरिका को खत्म करने का फैसला लिया था, जिसे कोलोराडो की अदालत ने अवैध ठहराया।

सथियों बात अगर हम भारत में पीएम को हटाए जाने के प्रावधानों की करें तो,किसी देश के प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए उसे निलंबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे में यहां हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या भारत में भी इस तरह से पीएम को लेकर कोई कार्रवाई संभव है?मभारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए रहता है। पीएम के कार्यकाल के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसीलिए एक पदस्थ पीएम अनिश्चित काल तक प्रधानमन्त्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो,इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति केवल तबतक पीएम पद पर बना रह सकता है, जब तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसके विपक्ष में न हो,लेकिन अन्य परिस्थितियों में पीएम का कार्यकाल पांच साल से पहले भी खत्म हो सकता है,भारत में भी निलंबित किए जा सकते हैं पीएमभारत किसी भी कारणवश लोकसभा, प्रधानमंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करे और किसी कारणवश,प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य हो जाती है तो उस वक्त पीएमअपने पद का त्याग कर सकता है और राष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र सौंप सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व में न्यायपालिकाओं का पावर–पीएम से लेकर एक आम नागरिक तक को कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक शक्तियों का डर एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? थाईलैंड की पीएम व डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू,इंदिरा गांधी सहित अनेकों अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को न्यायपालिका के फैसलों का सामना करना पड़ा है न्यायपालिकाओं की न्यायिक प्रक्रिया में खास से आम तक सभी व्यक्तियों को एक समान संहिता से लागू होकर सजा या बरी होना खूबसूरती है।

लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार
एडवोकेट किशन सनमुखदास
भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 3

अब प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग से हटकर हरित विकल्पों की ओर बढ़ें: वन मंत्री सुबोध उनियाल

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। बीआईएस देहरादून ने मंगलवार को देहरादून में पेपर और प्लास्टिक पैकेजिंग मानकों पर केंद्रित मानक मंथन कार्यक्रम का किया आयोजन।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखण्ड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इसके अलावा पैकेजिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अपने संबोधन में सुबोध उनियाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग से हटकर हरित विकल्पों की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा, "उत्तराखण्ड जैवविविधता से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ प्लास्टिक और नॉन–बायोडिग्रेडेबल सामग्री का प्रभाव अधिक गंभीर होता है। इसलिए पर्यावरण–अनुकूल पैकेजिंग अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है।" उन्होंने बीआईएस द्वारा तैयार किए गए मानकों की सराहना करते हुए कहा कि ये मानक केवल गुणवत्ता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और टिकाऊ विकास के उद्देश्य से भी जुड़े हुए हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते वन मंत्री।

श्री उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को हरित तकनीक अपनाने हेतु नीति, प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने उद्योगों से आह्वान किया कि वे बीआईएस के साथ मिलकर पर्यावरण–अनुकूल मानकों को अपनाएं। उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार की ओर से बीआईएस को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे बीआईएस के मानकों को अपनाएं और राज्य को हरित राज्य के रूप में स्थापित करने में योगदान दें।

उन्होंने कहा कि "मानक मंथन जैसे कार्यक्रम नीति और उद्योग के बीच संवाद की एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हरित भविष्य की दिशा में कदम है।" निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून सौरभ तिवारी ने मानक मंथन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक तकनीकी विमर्श नहीं, बल्कि उद्योग जगत और नीति–निर्माताओं के बीच एक सक्रिय संवाद की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय संकट के इस दौर में पैकेजिंग अब केवल उत्पाद की सुरक्षा या प्रस्तुति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। श्री तिवारी ने बीआईएस द्वारा विकसित किए गए प्रमुख मानकों 2771 (नालीदार फाइबरबोर्ड बॉक्स), 1397 (क्राफ्ट पेपर), और 11805 (दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग हेतु पॉलीइथिलीन पाउच) इत्यादिकृ का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मानक उद्योगों को पर्यावरण–अनुकूल समाधान अपनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

रिवर्स पलायन के प्रेरणादायक उदाहरण बने गुंज्याल और नेगी: मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) बिमला गुंज्याल के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की गुंजी ग्राम पंचायत तथा पूर्व कर्नल यशपाल सिंह नेगी के जनपद पौड़ी की बिरगण ग्राम पंचायत के निर्विरोध ग्राम प्रधान निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसे रिवर्स पलायन का एक प्रेरणादायक और सुखद उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का ग्राम प्रधान चुना जाना पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देगा और उनके अनुभव से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गुंजी और बिरगण ग्राम पंचायतें मॉडल ग्राम के रूप में उभरेंगी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस प्रकार के उदाहरण दर्शाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति अपने अनुभव और सेवा भावना से गांव की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है।

युद्धस्तर पर जारी है राज्य की 124 अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम: सतपाल महाराज

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। राज्य में मानसून सीजन 2025–26 में बरसात एवं भूस्खलन के कारण 154 सड़कें अवरुद्ध हैं इनमें से 08 जुलाई तक 30 सड़कें यातायात हेतु खोली जा चुकी हैं जबकि अन्य 124 सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य में मानसून सीजन में अत्यधिक बरसात एवं भूस्खलन के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोनिवि की 67 सड़कें बंद थी जिनमें से 12 को खोल दिया गया है और 55 सड़कों को खोलने का काम चल रहा है। इसी प्रकार राज्य में एनएच की 02, बीआरओ की 01, एनएचआईडीसीएल की 01 सड़क बंद है। जबकि पीएमजीएसवाई की 83 सड़कों में से 16 सड़कों को खोल दिया गया है। प्रदेश की अवरुद्ध 154 सड़कों में से 30 सड़कों को यातायात हेतु खोल दिया गया है। लोनिवि मंत्री श्री महाराज ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून के दौरान सभी अपने–अपने फोन एवं मोबाइल अवश्य उठायें ताकि मार्ग अवरुद्ध होने की सटीक जानकारी लोगों को समय से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यदि कोई सड़क बंद होती है तो उसकी पूर्व सूचना यात्रियों को पहले ही उनके पूर्ववर्ती स्टेशन पर मिल जानी चाहिए और उनसे वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें।

महंत इन्दिरेश अस्पताल ने चौशायर होम्स में आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून के द्वारा चौशायर होम्स, प्रीतम रोड, डालनवाला में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 105 पुरुष और महिला रोगियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

शिविर का शुभारंभ चौशायर होम्स के चेयरमैन डॉ. वेद प्रकाश पाठक द्वारा किया गया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज विशेष बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए सदैव समर्पित रहे हैं, यह शिविर भी उसी सेवा भावना का प्रमाण है। शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने रोगियों को परामर्श दिया और कई आवश्यक जांचें जैसे ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आदि निःशुल्क की गईं। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल, देहरादून के मेडिसिन विभाग के डॉ0 साहिल गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉ0 सिमरन डांग, नाक कान गला रोग विभाग की डॉ. दीक्षा लोहानी, नेत्र रोग विभाग के डॉ0 पलाश बाउड़ी व शिशु एवं बाल रोग विभाग के डॉ0 मोहम्मद शाबान ने रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श दिए। इस शिविर को सफल बनाने में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के उप वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर गौड़, जनसंपर्क अधिकारी दिनेश रतूड़ी एवं चौशायर होम्स की ओर से चेयरमैन डॉ. वेद प्रकाश पाठक, सचिव प्रदीप श्रीवास्तव, भूपेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।

शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्साकर्मी।

उत्तराखंड में चीन सीमा पर अमरनाथ जैसी बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति मिली

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। उत्तराखंड में चीन सीमा पर अमरनाथ जैसी बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति मिली है। उत्तरकाशी के नेलांग घाटी क्षेत्र में पर्वतारोहण अभियान के दौरान स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) के एक दल ने इसे खोजा है।

शिवलिंग के पास नदी जैसी आकृति भी एसडीआरएफ दल को मिली है। एसडीआरएफ ने इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है। सरकार ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई तो उत्तराखंड में भी अमरनाथ जैसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जा सकती है। उत्तराखंड में ट्रैकिंग की नई संभावनाएं तलाशने के लिए अप्रैल में एसडीआरएफ का एक 20 सदस्यीय दल नेलांग घाटी की दुर्गम चोटियों को फतह करने के लिए गया था। एसडीआरएफ दल ने नेलांग में नीला पानी क्षेत्र में 6,054 मीटर की एक ऐसी अनाम चोटी को फतह किया, जहां अब तक कोई पर्वतारोहण दल नहीं पहुंचा। इस चोटी पर करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से बनी शिवलिंग की आकृति दिखाई दी। अमरनाथ में शिवलिंग करीब 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं नीलापानी में जिस पर्वत पर यह आकृति मिली उसकी ऊंचाई 6,054 मीटर है। शिवलिंग की आकृति करीब 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है।

शिवलिंग की आकृति।

गंगोत्री से 10 किलोमीटर पहले लंका पुल के पास से नेलांग वैली के लिए सड़क मार्ग है। यहां तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। नेलांग से नीला पानी तक किसी वहां से पहुंचने के बाद यह दुर्गम ट्रैक शुरू होता है। इस मार्ग की शुरुआत ही बर्फीले रास्ते से होती है करीब 4.30 किलोमीटर की बर्फ के बीच खड़ी ट्रैकिंग के बाद शिवलिंग जैसी आकृति वाले स्थान पर पहुंचा जा सकता है। लॉन्ग वाली में भी पर्वती कुंड स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग और साहसिक खेलों के लिए नए स्थल विकसित करने का निर्देश राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर दिया था। इसके बाद राज्य की उन चोटियों पर एसडीआरएफ की टीम जा रही है, जहां अभी तक मानवीय गतिविधियां नहीं हुई हैं।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 4

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति बोर्ड बैठक में 127 करोड़ के बजट का अनुमोदन

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में समिति के कैनाल रोड स्थित कार्यालय सभागार में हुई। भगवान श्री बदरीविशाल तथा भगवान श्री केदारनाथ की आरती के साथ बैठक की शुरुआत हुई।

बैठक में सर्वप्रथम नवनियुक्त सदस्यों का परिचय हुआ साथ ही पदाधिकारियों तथा सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अब तक सफलतापूर्वक चल चारधाम यात्रा कुशल मार्गदर्शन हेतु प्रदेश सरकार तथा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया। बैठक का संचालन करते हुए बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने नवगठित बीकेटीसी की पहली बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया इसके बाद वित्त अधिकारी मनीष कुमार

बीकेटीसी बोर्ड बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व सदस्य।

उप्रेती ने बजट मंदिर समिति बोर्ड के समक्ष रखा बैठक में चर्चा के बाद मंदिर समिति के वर्ष 2025–26 के बजट का अनुमोदन किया गया।घ

श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्री बदरीनाथ धाम तथा श्री केदारनाथ धाम हेतु कुल 1,270999070 (एक सौ सत्ताईस करोड़ नौ लाख निन्यानबे हजार सत्तर) रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। श्री बदरीनाथ धाम हेड 64,2227070 (चौसठ करोड़ बाईस लाख सत्ताईस हजार सत्तर रुपये) का बजट प्रावधान किया गया है. इसे प्रस्तावित आय माना गया है।

श्री केदारनाथ धाम हेड 628770000 (बासठ करोड़ सत्तासी लाख सत्तर हजार रुपये बजट प्रावधान किया है। यह बजट में प्रस्तावित आय है। आय के सापेक्ष श्री केदारनाथ धाम हेतु 409337000 चालीस करोड़ तिरानबे लाख सैंतीस हजार रुपये व्यय दिखाया गया है इसी तरह श्री बदरीनाथ धाम हेतु प्रस्तावित आय के सापेक्ष 568683320 (छप्पन करोड़ छियासी लाख तिरासी हजार तीन सौ बीस रुपये व्यय दिखाया गया है।

बताया कि श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में 8 जुलाई 2025 तक 2478963 (चौबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिये है।

जिनमें से श्री बदरीनाथ धाम में 1137628 (बारह लाख सैतीस हजार छ सौ अठाइस श्रद्धालुओं ने दर्शन किये है तथा श्री केदारनाथ धाम में 1341335 (तेरह लाख इकतालीस हजार तीन सौ पैंतीस तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किये हैं। श्री बदरीनाथ धाम हेतु अभी तक 1432983 पजीकरण हुए है तथा श्री केदारनाथ धाम हेतु 1549930 तीर्थ यानियों ने पंजीकरण करवाया है। चारों धामों में यात्रा सुचारु है तथा मानसून के मौसम में यात्रा सतत चल रही है।

इंडिया हेल्थ फिर लौटा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव को देगा रफ्तार

देहरादून। अपनी शानदार शुरुआत के बाद, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया 11 से 13 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया हेल्थ प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण आयोजित करने के लिए तैयार है।

हेल्थकेयर में नए आविष्कारों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया हेल्थ 2025 स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाएगा, जिसे संपर्क बनाने, व्यवसाय बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए तैयार किया गया है। यह आयोजन विश्व प्रसिद्ध डब्ल्यूएचएब्स दुबई (पहले अरब हेल्थ) की विरासत से शुरू हुआ है और तेजी से भारत का प्रमुख हेल्थकेयर प्रदर्शनी और सम्मेलन मंच बन रहा है।

भारत का हेल्थकेयर क्षेत्र 2027 तक 18.5 बिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में, यह शो उद्योग की समावेशी, तकनीक आधारित और बड़े पैमाने पर हेल्थकेयर समाधानों की जरूरतों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।

पुलिस ने कार से ले जाई जा रही 06 पेटी अवैध शराब बरामद की, आरोपी गिरफ्तार

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। जनपद चमोली में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार निगरानी व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कोतवाली कर्णप्रयाग में गौचर पुलिस टीम द्वारा भट्टनगर जाने वाले मार्ग पर आल्टो कार से ले जाई जा रही 05 पेटी अवैध शराब प्चचमतपंस ठसनमूीपेाल व 01 पेटी बियर ठमम लवनदह कुल 06 पेटी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान, राहुल बिजल्वाण पुत्र मदन लाल बिजल्वाण निवासी ग्राम सुदाडा पोस्ट बहेडा थाना चम्बा टिहरी गढवाल (उम्र 29 वर्ष), पुलिस ने अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 60ध्72 के तहत

मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मानवेन्द्र सिंह गुसांई, हे0का09 प्रदीप बहुखण्डी, हे0का0 103 अशोक रावत, का0 260 सन्तोष बिष्ट शामिल रहे। एसपी चमोली श्री सर्वेश पंवार के निर्देशन में पंचायत चुनावों के दृष्टिगत अवैध मादक पदार्थों, शराब, नकदी व अन्य गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखी जा रही है। लगातार चेकिंग अभियान, पेट्रोलिंग और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त व पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकें।

महानगर व्यापार मंडल की संयुक्त व्यापार एकता मंच की बैठक आयोजित

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने संयुक्त व्यापारी एकता मंच के माध्यम से सभी व्यापारियों से वार्तालाप करते हुए कहा कि आप लोगों की जो टैक्स को लेकर जो भी विषय हैं वह सभी विषय विचारणीय है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सभी व्यापारियों के सहयोगी सरकार है हमारी सरकार के द्वारा लगातार समय–समय पर व्यापारियों को सहयोग देने का काम किया है आने वाले समय में भी हम सब व्यापारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं यह जो टैक्स का विषय है इस टैक्स के विषय को लेकर देहरादून नगर निगम के महापौर एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बैठकर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा

बैठक में मंचासीन पदाधिकारी।

जो व्यापारियों के हित का होगा मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक व्यापारी के विषय को लेकर चिंतित रहते हैं चाहे वह छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा व्यापारी मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अग्रिम आदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे। कार्यक्रम में संयोजक सुभाष चन्द्र भट्ट जी, हर्रावाला व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, नत्थनपुर प्रथम व्यापार संघ से अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, नत्थनपुर द्वितीय व्यापार संघ के अध्यक्ष दीपक नेगी, सम्मानित व्यापारी गणों में सविता पंवार, शालिनी रावत, एडवोकेट अनिल मैखुरी, जगदीश सेमवाल, (पूर्व पार्षद), विनय नेगी, ममता बिष्ट, प्रभा भंडारी गुंसाई आदि व्यापारी समाज उपस्थित रहा।

मुनकटिया में आये दिन बंद हो रहा सोनप्रयाग-गौरीकुंड मोटरमार्ग, सिरोबगड़ डेंजर जोन भी बन रहा जानलेवा

रुद्रप्रयाग (नजरिया खबर ब्यूरो)। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है, वहीं बद्रीनाथ व केदारनाथ हाईवे पर भी जगह–जगह बोल्डर व मलबा गिर रहा है, जिस कारण चारधाम यात्रियों को भी भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है।

केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने का सिलसिला लजगातार जारी है, जिससे केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका

उफनते नदी–नाले।

जा रहा है। वहीं बदरीनाथ हाईवे सिरोबगड़ में बंद हो रहा है। राजमार्गों को खोलने को लेकर एनएच विभाग की ओर से कार्यवाही गतिमान है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मानव जीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त है। मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश के अलावा भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा व मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग स्थित संगम स्थल का निचला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बारिश और भूस्खलन में सबसे अधिक दिक्कतें चारधाम यात्रियों को हो रही हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ों से लगातार गिर रहे बोल्डर के कारण यात्रियों को जगह–जगह फंसना पड़ रहा है। केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग–गौरीकुण्ड के बीच मुनकटिया में पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। यहां पर पहाड़ी से बड़े–बड़े बोल्डर और मलबा गिरा है, जिस कारण प्रशासन को कुछ घंटों के लिये तीर्थ यात्रियों को रोकना पड़ रहा है और मौसम साफ होने के बाद ही यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। हर दिन राजमार्ग के मुनकटिया में मार्ग बंद होने से तीर्थ यात्री खासे परेशान है। इसके साथ ही गौरीकुंड–केदारनाथ पैदल मार्ग भी जानलेवा बना हुआ है। पैदल मार्ग के जगह–जगह मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 5

चमोली में पोषण ट्रैकर समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में पोषण ट्रैकर ऐप की प्रगति हेतु जिलाधिकारी वीसी कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चिन्हित कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या, स्वास्थ्य स्थिति तथा सुधार के प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सीडीपीओ यह सुनिश्चित करें कि आँगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जा रहे संपूरक पोषण आहार की गुणवत्ता व मात्रा मानक अनुसार हो। उन्होंने कहा बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर आँगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति, कार्य संचालन, उपस्थिति रजिस्टर व गतिविधियों की निगरानी करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सभी आँगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन व ऊँचाई की नियमित माप, संपूरक पोषण और आहार की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जाए। इस दौरान सीडीपीओ जोशीमठ अभिजीत कुमार को मीटिंग में आवश्यक जानकारी ना देने पर नाराजगी व्यक्त की और मीटिंग में पूर्ण तैयारी के साथ बैठने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी आँगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पोषण ट्रैकर पोर्टल पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का डेटा समयबद्ध रूप से अपलोड किया जाए।उन्होंने कहा चिन्हित कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा की जाए तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण व फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु बडोला द्वारा अवगत कराया गया कि पोषण ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से जिले में कुल 17234 बच्चों को ट्रैक किया जा रहा है, जिनमें से जून माह में 186 बच्चे कुपोषित तथा 45 अति कुपोषित की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया इन बच्चों को संपूरक पोषण आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं विशेष देखरेख के माध्यम से पोषण स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ,सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी वी सी के माध्यम से उपस्थित रहे।

मजदूर योजनाओं का लाभ उठाएं: गीता सोनी

मुंगेली,बिलासपुर। भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ की बैठक ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बाघमुडा उद्यान (नर्सरी) के प्रांगण में आयोजित हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुंगेली जिला प्रभारी गीता सोनी थीं। अध्यक्षता अध्यक्ष सुमित सोनवानी ने की।

गीता सोनी ने कार्य विस्तार एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं की जानकारी दी और आगामी अधिवेशन पर विचार विमर्श किया। बैठक में निर्माण श्रमिक एवं संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व महामंत्री समेत 35 लोग उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की मौजूदा समस्याओं, पंजीयन प्रक्रिया में आ रही अड़चनों तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना था। अपने संबोधन में गीता सोनी ने कहा कि निर्माण श्रमिकों को आज भी अनेक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसका मुख्य कारण सूचना का अभाव और विभागीय लापरवाही है। उन्होंने पंजीयन, नवीनीकरण, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, एवं शिक्षा सहायता जैसी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि जल्द ही जिले में विशेष शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा।

चमोली में नामांकन पत्रों की जांच में 2680 आवेदन पाए वैध, 26 नामांकन पत्र निरस्त

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य आज दूसरे दिन को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों की ओर से 4382 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। जिनमें से 2680 नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गए हैं। जबकि 26 नामांकन पत्रों को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया। बुधवार को शेष नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी।

नामांकन पत्रों की जांच के बाद वर्तमान तक ग्राम प्रधान पद हेतु 1490, ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु 596, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु 594 नामांकन वैध पाए गए हैं,जबकि 26 निरस्त किये गए, नामांकन पत्रों में 15 सदस्य ग्राम पंचायत के, 8 प्रधान ग्राम पंचायत के और 3 सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का नामांकन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया है। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच, 10 व 11 जुलाई को नामवापसी की तिथि तय की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच व नामवापसी की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। जिसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में चल रहे प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को गंभीरता और सजगता से संपन्न कराया जाए।

प्रशिक्षण सत्र में प्रथम मतदान अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। मतपेटी की सीलिंग, मत पत्र लेखा, टेंडर वोट, अभिकर्ता नियुक्ति, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदाता पर्ची और मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षकों द्वारा दी गई। सत्र में कुल 920 कार्मिकों ने प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव मानसून सत्र में हो रहे हैं, ऐसे में आपदा या बारिश की स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी किसी इमरजेंसी परिस्थिति में है तो उसे चुनाव ड्यूटी में उचित राहत दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर मतदान कार्मिकों को समय से ड्यूटी की जानकारी दे दी जाएगी, जिससे वे तैयारी के साथ निर्वाचन कार्य में भाग ले सकें। उन्होंने सभी कार्मिकों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की।

जमरानी नहर के निर्माण कार्य के दौरान बिजली विभाग के चार विशालकाय पोल गिरे, विद्युत आपूर्ति ठप

लालकुआं (नजरिया खबर ब्यूरो)। हल्द्वानी से लालकुआं के बीच बनाई जा रही जमरानी नहर के निर्माण के दौरान खुदाई करते समय विद्युत विभाग की 11000 केवीए की विद्युत लाइन के चार पोल जमीन में गिर गए, जिसके चलते लालकुआं और हल्दूचौड़ समेत कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप्प हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर लगभग 3 बजे बबूर गुम्टी के समीप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की दीवार के समीप से बनाई जा रही जमरानी नहर के निर्माण के दौरान जब मजदूर जेसीबी मशीन एवं हाथों से जमीन खोद रहे थे तभी अचानक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बाउंड्री वॉल से सटकर जा रही 11000 केवीए विद्युत लाइन के चार विद्युत पोल जिसमें तीन सिंगल और एक डबल विद्युत पोल है, अचानक जमीन में गिर गए, सौभाग्य से इस दौरान लाइन ट्रिप हो जाने से विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई, और जमरानी नहर का काम कर रहे मजदूर बाल–बाल बच गए, एक साथ चार विद्युत पोल गिर जाने से क्षेत्र में अफरा– तफरी मच गई, आनन–फानन में विद्युत विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ संजय प्रसाद और अवर अभियंता इंतजार अली ने उक्त जमीन में गिर गए विद्युत पोलों को दुरुस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी, मौके पर मौजूद जमरानी नहर का निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों ने बताया कि विशालकाय सेमल का पेड़ विद्युत लाइन के ऊपर गिर जाने के चलते चार विद्युत पोल पेड़ के साथ ही जमीन में गिर गए, जिसके चलते उक्त घटना घटित हो गई, एसडीओ संजय प्रसाद ने कहा कि एक साथ चार विद्युत पोल गिर जाने के चलते लालकुआं के विभिन्न क्षेत्रों, आइटीबीपी समेत हल्दूचौड़ क्षेत्र के कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई है, तथा पोल उठाने की कार्रवाई विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में की जा रही है। और आज आधी रात बाद तक उक्त लाइन दुरुस्त हो पाएगी। फिलहाल देर शाम तक क्षेत्र में अंधकार फैला हुआ था।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 6

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया। जिस पर समिति द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुख्य सचिव बैठक लेते हुए।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत है गणियागांव पट्टी गगवाडस्युँ एवं ग्राम देवार पट्टी सीतोनस्यूं में एनसीसी अकादमी के निर्माण कार्य के लिए 7598.07 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विधानसभा में मुनि की रेती स्थित राम झूला सेतु के स्ट्रेंग्थनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु 1097.72 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया।

पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में टाइप–दो (ब्लॉक ए) के 120 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 5253.75 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया।

पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में टाइप–2 (ब्लॉक बी) के 120 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 5207. 47 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में टाइप टू (ब्लॉक सी) के 120 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 5214.91 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। जिला कारागार हरिद्वार में द्वितीय चरण में टाइप – थर्ड के 5 एवं टाइप सेकंड के 50 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 2125.72 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। जिला कारागार देहरादून में द्वितीय चरण में टाइप सेकंड के 60 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 2165.33 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव ने इस दौरान निर्देश दिए कि अनुमोदित किए गए सभी प्रस्तावों के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करें तथा उनको निर्धारित टाइमलाइन में पूरा भी करें। इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी, पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा आदि उपस्थित थे।

ओयूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण 26 जुलाई तक होगा निःशुल्क

चमोली। उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बीते 27 जनवरी 2025 से लागू की गई है। जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था।

वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। चमोली में वर्तमान तक यूसीसी के तहत 13 हजार 724 दम्पति की ओर से विवाह पंजीकरण किया गया है। जबकि 219 आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है तथा विभिन्न कारणों से 647 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जिले में विवाह विच्छेदन के 22 प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 19 का पंजीकरण हो गया है। जबकि 3 आवेदन निरस्त किए गए हैं।

हरिद्वार के घाटों, नीलकंठ महादेव मंदिर आदि प्रमुख स्थलों पर एम्बुलेंस व बैकअप की व्यवस्था होगी

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के घाटों, नीलकंठ महादेव मंदिर अन्य प्रमुखस्थलों पर एम्बुलेंस व बैकअप की व्यवस्था करने, सादे वस्त्रों में महिला व पुरुष सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती करने और आपदा राहत उपकरणों से युक्त गोताखोरों व जल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखने को कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे व लाउडस्पीकर के उपयोग को नियमबद्ध किया जाए। कांवड़ यात्रियों को 'क्या करें और क्या न करें' की जानकारी पेम्फलेट, होर्डिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को लाठी, डंडा, नुकीली वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने हेतु प्रचार अभियान चलाने को कहा। यात्रा मार्गों में मादक पदार्थों, शराब एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और समुचित बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए महिला घाटों और धर्मशालाओं में विशेष पुलिस प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया। अंतर्राज्यीय समन्वय बढ़ाकर सूचनाओं का तत्काल आदान–प्रदान करने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और संबंधित पोस्टों का तत्काल खंडन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

तलवाड़ी स्थित लाटू मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर मनौतियां मांगी

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। तलवाड़ी स्थित लाटू मंदिर मे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मनौतिया मांगी, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया गोपाल सिंह फर्शवाण को अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट को सचिव चुना गया।

विकासखंड थराली के तलवाड़ी स्थित लाटू मंदिर मे गुडम स्टेट के श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा अर्चना कर मनौतिया मांगी कुलगुरु गिरीश चंद्र जोशी ने बताया तलवाड़ी के लाटू मंदिर के कपाट वैशाख पूर्णमासी के दिन खोले गए थे तब गांव वासियों द्वारा समय अभाव के कारण एकजुट नहीं हो पाए आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के अवसर पूरे गांव द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया वही मंदिर समिति द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सर्व समिति से हर्ष सिंह सेजवाल को सरक्षक गोपाल सिंह फर्शवाण को अध्यक्ष, हरपाल सिंह रावत को उपाध्यक्ष, अवतार सिंह बिष्ट को सचिव, भगोत सिंह बिष्ट को कोषाध्यक्ष, आनंद सिंह बिष्ट, इंद्र सिंह फर्शवाण, राजा चौहाँन, कलम सिंह बिष्ट, गजेंद्र रावत, भरत बिष्ट, को सदस्य निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह बिष्ट,दयाल सिंह शाह, हर्ष सिंह सेजवाल,कलम सिंह बिष्ट, अवतार सिंह, क्लावती देवी, रेखा देवी आनंद सिंह बिष्ट, इंद्र सिंह फर्शवाण, गोपाल सिंह फर्शवाण, नोमी देवी, हरि रावत, भगवत सिंह बिष्ट, सावत्री देवी, बसंती देवी बिष्ट, गंगा देवी पुष्पा देवी राधा देवी पूनम बिष्ट, बबिता रावत, गणेशी देवी खुसबू पांगती, दीपा देवी,आदि मौजूद रहे।

रीजनल पार्टी ने किया 200 बीघा वन भूमि कब्जाने का खुलासा, लगाया आरोप

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भू माफियाओं के साथ साँठगाँठ कर अवैध तरीके से वन विभाग की 200 बीघा से ज्यादा अधोईवाला देहरादून की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया।

पत्रकार वार्ता के दौरान रीजनल पार्टी के पदाधिकारी।

सेमवाल ने कहा कि अधूरी वाला लाडपुर के खसरा नंबर 1075 की 200 बीघा वन भूमि पर छोटे–छोटे प्लाट काट कर बाहरी समुदाय के लोगों को बसा दिया गया है। इससे क्षेत्र की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। इसके बावजूद न तो वन विभाग अपनी भूमि का सीमांकन करा रहा है और न ही मानचित्र को दुरुस्त करने की जहमत उठा रहा है। यहां तक कि इन कब्जों के बारे में वन विभाग ने अपनी उच्च अधिकारियों को भी अवगत नहीं कराया। उत्तराखंड प्रेस क्लब में एक वार्ता करते हुए राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी से जमीनों को कब्जा मुक्त कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ईष्टवाल ने कहा कि एक तरफ सीएम धामी कहते है प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने नहीं दूँगा लेकिन दूसरी तरफ उनके अधिकारियों की ही मिलीभगत से वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। योगेश ईष्टवाल ने कहा कि इस संबंध में एसडीएम से लेकर जिला अधिकारी तक कई बार अवगत कराया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने मांग की है कि जब तक उक्त संपूर्ण आरक्षित वन भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो जाती तब तक उक्त भूमि में रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।

योगेश ईष्टवाल ने वन भूमि कब्जाने के मामले में तत्कालीन सर्वेयर नरेंद्र सिंह नेगी से लेकर वन संरक्षक आदि अन्य तमाम अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल ने कहा कि अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी सड़क से लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ेगी।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 7

अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान व हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन

गैरसैंण स्थित शोध संस्थान और एसआरएचयू जौलीग्रान्ट मिलकर करेंगे अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण पर संयुक्त कार्य

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण को नीति, नवाचार और अनुसंधान का केंद्र बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई।

यह रणनीतिक समझौता उत्तराखंड विधान सभा की अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण की दूरदर्शी सोच, प्रभावशाली नेतृत्व और सक्रिय पहल का परिणाम है। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, भराड़ीसैंण–गैरसैंण के बीच एक महत्वपूर्ण आपसी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पेयजल, जल स्रोत प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण नवाचार, सामुदायिक शासन व्यवस्था में सहभागी कार्यनीति और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। एमओयू पर विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार कमांडर चल्ला वेंकटेश्वर (से.नि.) और शोध संस्थान की ओर से सचिव हेम चंद्र पंत ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बोलते हुए विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने कहा कि यह समझौता केवल दो संस्थाओं के बीच नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा को तय करने वाला कदम है। उन्होंने कहा, "हमारा सपना है कि भराड़ीसैंण केवल एक प्रशासनिक राजधानी न रहकर एक ऐसा केन्द्र बने जहाँ नीति, विज्ञान, शोध और परंपरा मिलकर उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान गढ़ें। हमारी कोशिश है कि यहां से ऐसी नीतियां निकलें जो हिमालयी राज्यों के लिए मार्गदर्शक बनें। यह समझौता एक 'पॉलिसी इनोवेशन हब' की नींव है।"

एमओयू साइन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष व अन्य।

उन्होंने यह भी कहा कि "यह साझेदारी विधायकों, वैज्ञानिक संस्थानों, प्रशासन और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। इससे हमारे नीतिगत फैसले केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहकर जमीन से जुड़े, व्यवहारिक और जन–संवेदनशील बन सकेंगे। भराड़ीसैंण को एक जन–केंद्रित नीति राजधानी के रूप में विकसित करना हमारा संकल्प है।''

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेन्द्र डोभाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, विज्ञान और समाज के बीच एक सेतु बनाना है। विश्वविद्यालय बीते तीन दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब यह अनुभव नीति–निर्माण की प्रक्रिया से जुड़कर अधिक व्यापक बदलाव लाएगा। इस समझौते के अंतर्गत दोनों संस्थाएं जलवायु–संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण, जलस्रोत पुनर्जीवन (स्प्रिंगशेड प्रबंधन), वर्षा जल संचयन, महिला नेतृत्व, पारंपरिक ज्ञान आधारित समाधान और समग्र स्वास्थ्य जैसे विषयों पर संयुक्त परियोजनाएं प्रारंभ करेंगी। साथ ही विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों, युवाओं और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, अध्ययन यात्रा, नीति संवाद और डिजिटल मंच का विकास किया जाएगा।

यह भागीदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करेगी और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग की संभावनाओं को भी विस्तार देगी। कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया गया कि भराड़ीसैंण–गैरसैंण को अब नीति, नवाचार और पारिस्थितिकीय शोध के एक सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ से भविष्य की योजनाएं आकार लेंगी। इस अवसर पर शोध संस्थान के सचिव हेम चंद्र पंत ने शोध संस्थान की भूमिका, उद्देश्य और भावी योजनाओं की जानकारी साझा की।

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्र डिजिटल बदलाव के लिए तैयार

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ट्रांसयूनियन सिबिल ने संयुक्त रूप से 'सहकार ट्रेंड्स' रिपोर्ट का पहला संस्करण 2025 क्रेडिट कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित यह रिपोर्ट दर्शाती है कि, मार्च 2025 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का कुल पोर्टफोलियो बैलेंस 2.9 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। मार्च 2020 के मुकाबले बीते पाँच वर्षों में इसमें 1.8 गुना की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में दो अंकों की दर से वृद्धि हुई है, जो उधारी की बढ़ती मांग और विस्तृत बाजार पहुँच के कारण संभव हो सकी है। तकनीक–आधारित बदलाव की दिशा में आह्वान के बीच न्ब्ठ सेक्टर एक मजबूत वित्तीय समावेशन के वाहक के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शहरी सहकारी बैंक तकनीक–आधारित पुनरुत्थान के जरिए अपने अगले विकास चरण के लिए तैयार हैं। डिजिटल परिवर्तन को तेजी से अपनाने और संचालन में आधुनिकता लाने की भरपूर संभावनाएँ मौजूद हैं। तकनीक पर केंद्रित रणनीतिक पहल न केवल इस सेक्टर की विकास गति को मजबूती देगी, बल्कि तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ाएगी। 'सहकार ट्रेंड्स' रिपोर्ट के पहले संस्करण में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

'आमि डाकिनी' में मीरा के किरदार के लिए अपने जीवन से प्रेरणा लेती हैं : राची शर्मा

मुंबई (ईएमएस)। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो 'आमि डाकिनी' दर्शकों का गहराई से भरी भावनाओं और परतदार कहानी की दुनिया में लगातार खींच रहा है। कोलकाता की पृष्ठभूमि पर रचे इस धारावाहिक में हर किरदार अपने भीतर प्यार, क्षति और अनकहे सच का बोझ लिए हुए है, जहाँ हुस्न भी है, मौत भी। इसी कहानी के केंद्र में हैं मीरा घोष, जिनका किरदार निभा रही हैं प्रतिभाशाली अभिनेत्री राची शर्मा। मीरा सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि अपने परिवार की भावनात्मक रीढ़ हैं। एक ऐसी महिला, जो कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन साधे हुए है।

राची शर्मा बताती हैं कि वह मीरा के सफर से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, "मीरा घोष बहुत बहादुर है, लेकिन उतनी ही भावुक भी। बहुत कम उम्र से ही वह अपने परिवार की ताकत बन गई, खासकर तब से जब उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया।

यही वजह है कि उनकी छोटी बहन उन्हें प्यार से 'मीरा माँ' कहती है, क्योंकि मीरा ने माँ की भूमिका निभाई और अपनी बहन की परवरिश की। वह अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है और उसमें एक अटूट 'कभी हार न मानने' वाला जज़्बा है। उसकी यह बात मुझसे बहुत मेल खाती है। मेरे पास एक छोटा भाई है, और मीरा की एक छोटी बहन। भाई–बहन का यह रिश्ता मेरे दिल के बहुत करीब है।"

मीरा के किरदार के माध्यम से राची शो में एक मजबूत और सच्ची भावनात्मक गहराई लेकर आती हैं, जो कहानी को एक सजीव और आत्मीय आधार देती है। जब शो हुस्न और परिणाम के बीच की महीन रेखा को छूता है, तब राची की परफॉर्मेंस उन सभी के दिल को छू जाती है, जिन्होंने अपनों के लिए लड़ना सीखा है। 'देखिए 'आमि डाकिनी', हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनीलिव पर'।

विवेचना की गुणवत्ता सुधार को डीजीपी ने ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊ रेंज सहित समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डीजीपी ने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों की विवेचना में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जांच रिपोर्ट, चार्जशीट एवं फाइनल रिपोर्ट आदि पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि अधिकतर अपराधों हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा सरल और अपराध–आधारित एस0ओ0पी0 तैयार की गई हैं, जिन्हें नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

डीजीपी बैठक लेते हुए।

उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों की जांच प्रक्रिया को लेकर की गई अपेक्षाओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि विवेचना सही एवं निष्पक्ष हो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन प्लान, वैज्ञानिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य आदि का समावेश होना नितान्त आवश्यक है। एक विवेचक को अभियोजन अधिकारियों से पूर्व समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि प्रभावी न्यायिक प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित हो सके। पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि थानों की विवेचनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण, कमियों की पहचान और समयबद्ध सुधार सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना पर विवेचक, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जाय। समस्त जनपद प्रभारियों द्वारा अपने–अपने सुझावों से अवगत कराया गया। मुख्यालय स्तर पर गोष्ठी में उपस्थित उच्चाधिकारियों द्वारा गहन चर्चा कर विवेचना की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपने अनुभव साझा किये।

डीजीपी ने निर्देश दिए कि नियमित रूप से ओ0आर0 के माध्यम से विवेचकवार विवेचना की गहन समीक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक जनपद में क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक स्तर तक अपराध समीक्षा की साप्ताहिक कार्ययोजना बनाई जाए। जांच प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी एवं इन्वेस्टिगेशन प्लान को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

10 July 2025_Copy of Layout 1 7/10/2025 1:07 PM Page 8

प्रत्येक लाभार्थी तक आयुष्मान का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता: अरविंद

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण व आयुष्मान, गोल्डन कार्ड सूचीबद्ध अस्पतालों की संयुक्त समीक्षा समन्वय बैठक हुई। बैठक में ऑनलाइन पोर्टल से लेकर दावों के यथा समय निस्तारण, अमान्य दावे, रिव्यू आदि विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। योजना के बेहतर संचालन हेतु कई सुझाव भी प्रतिभागियों ने साझा किए।

प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी बैठक लेते हुए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे, यह हम सबकी प्राथमिकता है। सदन में उपस्थित अस्पताल प्रतिनिधियों व ऑनलाइन जुड़े प्रतिनिधियों को बारी बारी से अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपने अस्पताल की विशिष्ट समस्या के साथ साथ अस्पतालों की सामान्य समस्याओं पर ध्यानाकर्षण किया। चेयरमैन ने कहा कि एनएचए के ट्रांजिक्शन मैनेमेंट सिस्टम (टीएमएस) में समय समय पर आ रही तकनीकी कठिनाइयों तथा रिव्यू सम्बन्धी नई व्यवस्था के कारण अस्पतालों के आयुष्मान सम्बन्धी दावों के निस्तारण में कुछ समय लगा है, लेकिन अब इसे शीघ्रता से कराया जा रहा है। आयुष्मान के दावों का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने का लक्ष्य रखकर ही कार्यवाही की जा रही है।

पुराने दावों के सापेक्ष पोर्टल में रिव्यू संबंधी कठिनाई के दृष्टिगत ऑफ लाइन रिव्यू का अवसर दिया जायेगा और दावों के रिव्यू सिस्टम को आसान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का अपना टीएमएस तैयार किया जा रहा है। तब टीएमएस में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कहा की प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और यथासंभव ऑनलाइन सिस्टम बनाकर उन्हें फेसलेस करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ताकि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो और अस्पतालों को प्राधिकरण का चक्कर न लगाना पड़े। चेयरमैन ने अस्पतालों से भी यह अपेक्षित है कि मरीजों की सुविधा और इलाज पर पूरा ध्यान दिया जाए और उपचार के बिल एनएचए और एसएचए के दिशा निर्देशों और मानकों के अनुरूप ही प्रक्रिया फॉलो करते हुए सही सही प्रस्तुत करें। ताकि आपत्ति न लगे और भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही कहा कि कामकाज में व्यवहारिकता का होना जरूरी है। सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा विशिष्ट प्रकरणों में सम्यक विचार करते हुए न्यायोचित निर्णय लिए जाएंगे। कहीं अस्पष्टता हो तो उसे एसएचए के संबंधित अनुभाग अथवा उच्च अधिकारियों को फोन करके स्थिति स्पष्ट करा सकते हैं। गोल्डन कार्ड में आ रही दिक्कतों पर उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में आवश्यक बजट की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही गतिमान है और शीघ्र ही स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। बैठक में प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि आयुष्मान योजना की बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि एसएचए व सेवा प्रदाता अस्पतालों के बीच बराबर समन्वय हो। बैठक में शामिल हिमालयन हॉस्पिटल, महंत इंद्रेश, कैलाश ओमेगा, ग्राफिक एरा, पैनेसिया हॉस्पिटल, हंस फाउंडेशन, समेत विभिन्न अस्पताल प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकांश का यथोचित निस्तारण मौके पर ही किया गया।

आयरन ट्रेडिंग फर्म पर राज्य कर विभाग की कार्रवाई, पांच करोड़ की कर चोरी पकड़ी

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। राज्य कर विभाग की विशेष अन्वेषण शाखा (एसआईबी) ने जीएसटी चोरी करने पर देहरादून में आयरन ट्रेडिंग फर्म पर कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में विभाग ने फर्जी बिल बना कर आईटीसी का लाभ लेकर पांच करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। राज्य कर आयुक्त सोनिका के दिशानिर्देश पर संयुक्त आयुक्त अजय कुमार की अगुवाई में एसआईबी ने आयरन स्टील फर्म पर कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि वास्तविक माल की आपूर्ति किए बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का लाभ लिया है।

ऐसे वाहनों से माल की आपूर्ति दिखाई गई, वह वाहन किसी भी टोल प्लाजा से नहीं गुजरे। जिन तारीख में ई–वे बिल बनाया गया, उस दिन माल वाहन की लोकेशन दूसरी जगह दिखाई दी। इसके अलावा ई–रिक्शा, कार, थ्री व्हीलर से 15 से 20 टन माल परिवहन दर्शाया गया, जो संभव नहीं है। उपायुक्त एसआईबी अजय बिरथरे ने बताया कि प्रारंभक जांच में फर्जी बिलों से पांच करोड़ का आईटीसी लाभ लेने का खुलासा हुआ है। इसमें फर्म ने मौके पर 1.35 करोड़ राशि जमा कराई है। शेष राशि की वसूली के लिए विभाग की ओर कार्रवाई की जा रही है। फर्म के टैक्स रिटर्न व कारोबार से संबंधित दस्तोवजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई में उपायुक्त डीआर चौहान, योगेश मिश्रा, सुरेश कुमार, सहायक आयुक्त टीका राम चन्याल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा

देहरादून। भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप तितौरिया अपने उत्तराखंड दौरे पर प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंचे। जहां उन्होने एक होटल पर पदाधिकारियों को बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से विक्रम भारद्वाज को उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और शीघ्र ही उन्हें अपनी कमेटी गठित कर अनुमोदन के लिए भेजने के लिए कहा गया। इस मौके पर तितौरिया ने उपस्थिति कार्यकर्ताओं से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर पहाड़ी राज्य में यूनियन को मजबूत कर गरीब, मजदूर व किसानों की आवाज बनने का आहवान किया। विक्रम भारद्वाज ने कहा कि जहां एक ओर पहाड़ों पर आपदा आने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है।

चमोली में अतिवृष्टि से मोक्ष नदी ने मचाया तांडव

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। प्रदेश में मानसून ने दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते आज भी अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी–नाले उफान पर हैं। जगह–जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक घटना बीते देर रात चमोली जनपद के नंदानगर विकासखंड क्षेत्र के धुर्मा, मोख, सेंतोली, कुण्डी क्षेत्र अतिवृष्टि की घटना देखने को मिली है। यहां भारी बारिश से हुई अतिवृष्टि से खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग इसे बादल फटना कह रहे हैं वहीं प्रशासन अतिवृष्टि मान रहा है। बता दें कि इस अतिवृष्टि का असर संपूर्ण मोख वैली में हुआ है, यहां मोक्ष नदी के समीप बसा गांव सेरा भी खतरे के जद में आ गया है। बताया जा रहा है कि सड़कें भी जगह जगह जमींदोज हो गई है। जिससे संपूर्ण घाटी का बाजार से संपर्क टूट गया है। नंदानगर विकासखंड में मोक्ष नदी उफान पर आने से सेरा गांव में नुकसान की खबर है और कई घरों में पानी घुस गया।

मोक्ष नदी।

न्यूज डायरी

नहाते समय भिलंगना नदी में बहा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा कोई सुराग

टिहरी। टिहरी में मंगलवार को भिलंगना नदी में नहाते समय एक युवक नदी की तेज धारा में बह गया। युवक की तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी में सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि चांजी मल्ली गांव निवासी तीन युवक दोपहर के समय सेमली बैंड के समीप भिलंगना नदी में नहाने गए थे। दोपहर तीन बजे के लगभग दो युवकों ने फोन कर सूचना दी की उनका एक साथी नदी में बह गया है। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वहां सर्च अभियान चलाया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनके साथ सचिन रावत (25) पुत्र महेंद्र सिंह नदी में नहा रहा था अचानक पैर फिसलने से वह नदी की तेज धार में बह गय। इस घटना की सूचना पर युवक की परिजन भी मौके पर पहुंचे। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि सचिन बंगलूरू होटल में नौकरी करता था और कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर गांव आया हुआ था। युवक की तलाश में कल फिर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस घटना से चांदी मल्ली गांव गांव में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो–रो कर बुरा हाल है

पेज 01 का शेष...

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे डीएम: धामी

राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन करते हुए रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष, तथा शांति मेहरा, नवीन वर्मा और हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों से विनम्र अपील है कि यदि आप जीवन–यापन हेतु उपेक्षित महसूस करते हैं, तो अविलंब अपने नजदीकी भरण–पोषण अधिकरण अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।

स्वत्वाधिकारी नजरिया खबर के लिए स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीता जायसवाल द्वारा श्रेष्ठा प्रिन्टर्स, वार्ड नं.03,पो.ओ. लालकुंआ जिला–नैनीताल, उत्तराखण्ड से मुद्रित तथा 14–डी मीडो प्लाजा, प्रथम तल राजपुर रोड देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित सम्पादक : विजय जायसवाल फोन नं. – 0135&2740930, 9837027458 RNI NO: UTTHIN/2008/25052 प्रकाशन सम्बन्धी सभी विवादों का निस्तारण सिर्फ देहरादून न्यायालय होगा। E-mail: nazariakhabar@gmail.com
Website : www.nazariyakhabar.com **डाक पंजीयन : UA/DO/DDN/402/2017-19**